संतुलन बनाने की सराहनीय कोशिश

सुको ने बहुचर्चित चार धाम प्रॉजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा करने की मंजूरी देते हुए देश की रक्षा चिंताओं और पर्यावरण चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की सराहनीय कोशिश की है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस प्रॉजेक्ट के तहत बनी सड़क भारत चीन सीमा तक साजो–सामान पहुंचाने का जरिया बनेगी।

नवीन पंडित।।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित चार धाम प्रॉजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा करने की मंजूरी देते हुए देश की रक्षा चिंताओं और पर्यावरण चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की सराहनीय कोशिश की है। चार धाम प्रॉजेक्ट मूलतः गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़कमार्ग से जोड़ने की योजना है, जिसका मकसद इन तीर्थों तक ऑलवेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित चार धाम प्रॉजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा करने की मंजूरी देते हुए देश की रक्षा चिंताओं और पर्यावरण चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की सराहनीय कोशिश की है। चार धाम प्रॉजेक्ट मूलतः गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़कमार्ग से जोड़ने की योजना है, जिसका मकसद इन तीर्थों तक ऑलवेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इसी रूप में इसे पेश किया जाता रहा है। जब इस प्रॉजेक्ट को अदालत में चुनौती दी गई, तब सुनवाई के दौरान इसका रक्षा से जुड़ा पहलू उभर कर आया। सरकार की ओर से बताया गया कि इस प्रॉजेक्ट के तहत बनी सड़क भारत चीन सीमा तक साजो–सामान पहुंचाने का जरिया बनेगी।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बाकायदा उदाहरण देकर बताया कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 42 फीट लंबी है। जाहिर है, इसे ले जाने के लिए सेना को बड़े वाहनों की जरूरत होगी। सड़क की चौड़ाई कम करने से वह मकसद पूरा नहीं होगा। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हाल में उभरे तनाव को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि सरहद तक सैन्य आपूर्ति का सुगम मार्ग उपलब्ध रहना कितना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही देश की सुरक्षा चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि इसकी तुलना अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के दूसरे प्रॉजेक्ट्स से नहीं की जा सकती। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पॉइंट उठाया गया कि सेना ने कभी सड़क चौड़ा करने की मांग नहीं की। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास सरकार की एक अहम स्थायी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि हर बार यह कार्य घोषित रूप में ही किया जाए। अक्सर यह अजेंडा अघोषित और गोपनीय रूप में भी आगे बढ़ाया जाता है।

बहरहाल, पर्यावरण से जुड़ा पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। खासकर हाल के दिनों में आई त्रासद आपदाओं ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि यह पूरा क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से कितना संवेदनशील है। स्वाभाविक ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की रक्षा जरूरतों को अहमियत देते हुए भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं की अनदेखी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो इस बात का ध्यान रखेगी कि प्रॉजेक्ट पर काम के दौरान पर्यावरण संबंधी तमाम दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

हालांकि समिति को नए सिरे से पर्यावरण संबंधी खतरों का आकलन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन वह अब तक के सभी निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने का काम करेगी।

ढलान है जिंदगी

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

संघर्ष, विघ्न, जिम्मेदारियां– यही तो खूबसूरती है जीवन की। कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। जिंदगी में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं। ये हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि हम उनसे भयभीत नहीं हैं, उनकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडीसन ने कहा है, 'हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना।' जो व्यक्ति आपत्ति–विपत्ति से घबराता नहीं, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है।

संपादकीय

लाभार्थियों का वर्ग

बीजेपी की संभावनाओं को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी की जीत को अवश्यंभावी मान लेना भी अभी जल्दबाजी होगा। सभी पार्टियों के नेता धार्मिक प्रतीकों और अपीलों की शरण लेते दिख रहे हैं। कुछ तो वोटरों के धार्मिक ध्रुवीकरण की भी कोशिशों में लगे हैं। बीजेपी नेता इससे पहले विभिन्न जातियों में हिंदू एकीकरण की भावना भरने में सफल रहे हैं। पार्टी मोदी सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के आधार पर लाभार्थियों का एक अलग वर्ग तैयार करने में भी कामयाबी हासिल कर चुकी है। यह इस बार भी इस पर जोर दे रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव राज्य के लिए अपना कोई वैकल्पिक विजन अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। वह विभिन्न जातियों के इंद्रधुनषी गठबंधन पर भरोसा किए बैठे नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने के बाद भी अगर यूपी में जीत जाती है तो राजनीतिक माहौल उसके पक्ष में हो जाएगा। हां, इसके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी नेताओं में होड़ भी बढ़ेगी। अगर इन नेताओं की यह राय 10 मार्च को चुनाव परिणाम के बाद सही साबित होती है तो इसका मतलब यह होगा कि वोटर दूसरी लहर के दौरान दिखी राज्य सरकार की नाकामियों की सामूहिक स्मृति से ज्यादा प्रभावित हुए और चुनावों से पहले की गई प्रचंड विज्ञापनबाजी से कम।

राज्य स्तर पर 2017 से ही यह नैरेटिव चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद में बड़े नेता हैं। उन्होंने विज्ञापनों, होर्डिंगों और बयानों के जरिए अपनी यह छवि बनाई है। यूपी अन्य बीजेपी शासित राज्यों से बिल्कुल अलग है भी।

योगी अधिक 'स्वायत्त'

नीलांजन मुखोपाध्याय।।

उत्तर प्रदेश बीजेपी से मंत्रियों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफों की झड़ी ने विधानसभा चुनावों के ऐन पहले अप्रत्याशित रूप से एक राजनीतिक मंथन को जन्म दे दिया है। यह स्थिति 2017 के चुनावों से पहले पार्टी में दिख रहे जोश से भरे माहौल के एकदम उलट है, जब दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेताओं की लाइन लगी हुई थी। तब पार्टी का सबसे बड़ा आकर्षण 'नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा बनना' और उस नए सामाजिक गठबंधन में शामिल होना था, जिसे तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। शाह इस प्रॉजेक्ट पर 2013 से ही काम कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी।

दशकों के प्रयासों के बाद 2014 के बाद से यह स्थिति बनी कि निचली ओबीसी जातियों और दलित उपजातियों का ठोस समर्थन बीजेपी के पक्ष में दिखने लगा। यह समर्थन हिंदुत्व की पृष्ठभूमि में विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर आधारित था। ऐसे में क्या इस पलायन का यह मतलब है कि बीजेपी का सामाजिक गठबंधन बिखरने के कगार पर आ गया है? मोदी और शाह आज भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी और सरकार में दो सबसे ताकतवर

हस्तियां हैं। लेकिन राज्य स्तर पर 2017 से ही यह नैरेटिव चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद में बड़े नेता हैं। उन्होंने विज्ञापनों, होर्डिंगों और बयानों के जरिए अपनी यह छवि बनाई है। यूपी अन्य बीजेपी शासित राज्यों से बिल्कुल अलग है भी। योगी आदित्यनाथ अन्य मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा 'स्वायत्त' हैं। हालांकि केंद्र और राज्य के बीच किसी तरह का मतभेद सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है, आज भी 'डबल इंजन' मॉडल चुनाव में यूएसपी बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद नहीं थे।

पिछले सप्ताह पार्टी छोड़ने वाले नेता मुख्यतरू योगी आदित्यनाथ के ही खिलाफ थे, उनकी कार्यशैली की आलोचना कर रहे थे। उनका गुस्सा केंद्रीय नेतृत्व से नहीं था क्योंकि राज्य में शासन और नीतियों से जुड़े सारे फैसले सीएम ही करते रहे हैं। ऐसे में अगर इस पलायन का कोई दुष्प्रभाव चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ता है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के सिर पर आएगी। इससे जहां 2024 के लिहाज से पार्टी के अंदर का समीकरण और ज्यादा अनुशासित, ज्यादा सीधा हो जाएगा वहीं विरोधियों का बढ़ा हुआ हौसला और पार्टी कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ मनोबल पार्टी की राह को और मुश्किल बनाएगा।

बहरहाल, हकीकत यह है कि इन इस्तीफों की एकमात्र वजह योगी आदित्यनाथ की सरकार चलाने की अतिकेंद्रीकृत शैली नहीं हो सकती। बीजेपी के जिन पूर्व नेताओं को अचानक ही यह अहसास हुआ कि योगी सरकार ओबीसी और दलित समाजों की उपेक्षा करती रही है, वे सब योगी की नीतियों को ही नहीं, काम करने के उनके अंदाज को और इस वजह से पैदा हो रहे उस राजपूत वर्चस्व को भी स्वीकार कर चुके थे जिससे ऊंची जातियां समेत अन्य सभी तबके अलग–थलग महसूस करने लगे। इन नेताओं का जाना बताता है कि दरअसल, उन्हें बीजेपी में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आ रहा था। उन्हें यह लगने लगा था कि बीजेपी छोड़ देना और खासकर समाजवादी पार्टी से जुड़ना उनके लिए अच्छा होगा। इससे उनकी यह राय भी स्पष्ट होती है कि प्रदेश में सत्ता विरोधी भावनाएं काफी मजबूत हो गई हैं।

अष्टयोग-4968

7		3			2	
	31		31		28	2
4		1		3		
5	28	6	31		39	3
		4			7	
3	29		32	7	40	5
	3	2	4		7	1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4967 का हल

6	3	2	4	5	7	1
2	27	7	32	4	34	2
4	2	1	6	3	5	7
5	28	6	31	6	39	3
1	5	4	3	2	7	6
3	33	5	31	7	34	5
7	5	3	6	1	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

बीजेपी को भगीरथ प्रयत्न करने होंगे

मोहन। तीसरी लहर का असर जैसे–जैसे बढ़ रहा है, धुंधली पड़ती इन स्मृतियों के फिर ताजा हो जाने के आसार भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को किसानों का गुस्सा भी झेलना है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उसके खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन भी तैयार हो चुका है।

मगर चुनावी नतीजे जो भी हों, यह पलायन बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। आखिर यह विनाशकारी दूसरी लहर के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव हैं। दूसरी लहर के कहर के दौरान सरकारी तंत्र की जो नाकामियां रहीं, उनमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी मानी जाती है। ऐसे में महामारी के दौरान राज्य सरकार की भूमिका से निराशा के कारण अगर बीजेपी के सामाजिक गठबंधन में दरारें उभरती हैं तो 2024 में इसकी भरपाई के लिए बीजेपी को भगीरथ प्रयत्न करने होंगे या पुलवामा जैसा कोई मुद्दा हाथ लग जाए तो उससे रातो–रात लोगों का मिजाज बदल सकता है।